भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3064

18 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

'अमृत' मिशन के कार्यान्वयन और परिणामों की स्थिति

†3064. श्री अनूप संजय धोत्रेः
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः
श्री मनोज तिवारीः
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः
श्री पी. सी. मोहनः
डॉ. हेमंत विष्णु सवराः
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः
श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहानः
श्री दामोदर अग्रवालः
कैप्टन बृजेश चौटाः
सुश्री कंगना रनौतः
श्री भर्तृहरि महताबः
श्री अनिल फिरोजियाः
श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गीः
श्री बिभु प्रसाद तराईः
श्री जुगल किशोरः
श्री गोडम नागेशः
श्रीमती स्मिता उदय वाघः
डॉ. विनोद कुमार बिंदः
श्रीमती अपराजिता सारंगीः
श्री नव चरण माझीः
श्री खगेन मुर्मुः
श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेलः
श्री यदुवीर वाडियारः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) और अमृत 2.0 के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली, कर्नाटक सहित विशेषकर दक्षिण कन्नड़ जिले और मंगलौर नगर निगम, मध्य प्रदेश, विशेषकर रतलाम लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्ट्र, विशेषकर जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और पालघर जिला के लिए जल आपूर्ति, सीवरेज, सेप्टेज प्रबंधन और स्टॉर्म-वॉटर निकासी परियोजनाओं की नवीनतम प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अमृत और अमृत 2.0 के अंतर्गत आबंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का कर्नाटक विशेषकर बंगलुरु और दक्षिण कन्नड़, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, विशेषकर जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों में पाइप द्वारा जलापूर्ति की पहुंच बढ़ाने, जल की गुणवत्ता में सुधार करने और सीवरेज कवरेज में वृद्धि करने पर अमृत और अमृत 2.0 के प्रभाव का कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे आकलनों के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और कर्नाटक सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, विशेषकर बंगलुरु और अन्य शहरों तथा महाराष्ट्र, विशेषकर जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए क्या सुधार दर्ज किए गए हैं; और

(ङ) अमृत और अमृत 2.0 के अंतर्गत कर्नाटक सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और जिला-वार, विशेषकर बंगलुरु, दक्षिण कन्नड़ जिले और अन्य शहरी स्थानीय निकायों, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र विशेषकर जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कितने जल निकायों और हरित क्षेत्रों का पुनरुद्धार किया गया है अथवा विकसित किया गया है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने अमृत के तहत 83,463 करोड़ रुपये की 6,008 परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से 80,469 करोड़ रुपये के कार्य भौतिक रूप से पूरे किए जा चुके हैं। जलापूर्ति क्षेत्र में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 43,359.78 करोड़ रुपये की 1,403 परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से 42,073.22 करोड़

रुपये के भौतिक कार्य पूरे किए जा चुके हैं; सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन क्षेत्र में, 34,459.46 करोड़ रुपये की 890 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 33,013.53 करोड़ रुपये के भौतिक कार्य पूरे किए जा चुके हैं; तूफानी जल निकासी क्षेत्र में, 3,016.82 करोड़ रुपये की 838 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 2,828.71 करोड़ रुपये के भौतिक कार्य पूरे किए जा चुके हैं। दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित अमृत योजना के अंतर्गत जलापूर्ति, सीवरेज, सेप्टेज प्रबंधन और तूफानी जल निकासी परियोजनाओं की राज्य-वार/ संघ राज्य क्षेत्र- वार प्रगति का विवरण अनुलग्नक - ।में दिया गया है।

अमृत 2.0 के तहत, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत 1,93,427.02 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 8,804 परियोजनाओं को अनुमोदन दिया जा चुका है, जिनमें 1,18,226.61 करोड़ रुपये की लागत वाली 3,516 जलापूर्ति परियोजनाएं और 67,840.59 करोड़ रुपये की लागत वाली 588 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं शामिल हैं। जलापूर्ति क्षेत्र में 77,504.05 करोड़ रु. की लागत वाली 2,859 परियोजनाएं तथा सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन क्षेत्र में 38,739.90 करोड़ रुपये की लागत वाली 433 परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। शेष परियोजनाएं निविदा/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के विभिन्न चरणों में हैं।अमृत 2.0 के तहत दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित जलापूर्ति और सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाओं की राज्य-वार प्रगति का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में, मंगलुरु शहर को अमृत के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसमें 35.52 करोड़ रु. की एक जलापूर्ति परियोजना तथा 3.66 करोड़ रु. की एक वर्षा जल निकासी परियोजना शुरू की गई थी, जिन्हें पूर्ण कर लिया गया है। अमृत के अंतर्गत 160.19 करोड़ रु. की तीन सीवरेज परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जिनमें से 98.31 करोड़ रु. के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। अमृत 2.0 के अंतर्गत 325.11 करोड़ रु. की 6 जलापूर्ति परियोजनाएँ प्रारंभ की गई हैं, जिनमें से 185.94 करोड़ रु. की परियोजनाओ का कार्य भौतिक रूप से पूर्ण कर लिया गया है।

मध्य प्रदेश के रतलाम लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में, रतलाम शहर को अमृत योजना में शामिल किया गया है, जिसमें 141.44 करोड़ रु. की एक सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन परियोजना और 13.53 करोड़ रु. की एक वर्षा जल निकासी परियोजना शुरू की गई थी, जो पूरी हो चुकी हैं। अमृत 2.0 के अंतर्गत 199.54 करोड़ रु. की 15 जलापूर्ति परियोजनाएँ अनुमोदित और शुरू की गई हैं, जिनमें से 75.06 करोड़ रु. के निर्माण कार्य भौतिक रुप से

पूर्ण किए जा चुके हैं; 48.40 करोड़ रु. की एक सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन परियोजना भी अनुमोदित एवं शुरू की गई है, जिसमें अब तक 1.19 करोड़ रु. के निर्माण कार्य भौतिक रूप से पूर्ण किए जा चुके हैं।

महाराष्ट्र के जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में अमृत योजना के अंतर्गत 344.09 करोड़ रु. की दो जलापूर्ति परियोजनाएँ प्रारंभ की गई हैं, जिनमें से 341.36 करोड़ रु. के निर्माण कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। अमृत 2.0 के अंतर्गत 987.48 करोड़ रु. की 13 जलापूर्ति परियोजनाएँ अनुमोदित की गई हैं, जिनमें से 841.81 करोड़ रु. की 12 परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं।

महाराष्ट्र के पालघर ज़िले में अमृत योजना के अंतर्गत 547.53 करोड़ रु. की 3 जलापूर्ति परियोजनाएँ प्रारंभ की गई हैं, जिनमें से 545.25 करोड़ रु. के निर्माण कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। अमृत योजना 2.0 के अंतर्गत 634.67 करोड़ रु. की 3 जलापूर्ति परियोजनाएँ अनुमोदित एवं शुरू की गई हैं, जिनमें से 240.68 करोड़ रु. के निर्माण कार्य भौतिक रूप से पूर्ण किए जा चुके हैं। अमृत 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत 529.74 करोड़ रु. लागत की एक सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजना भी प्रारंभ की गई है, जिसमें से 86.82 करोड़ रु. के कार्य भौतिक रूप से पूर्ण किए जा चुके हैं।

अमृत और अमृत 2.0 के तहत, केंद्रीय सहायता मिशनों की शुरुआत में ही आवंटित की गई है, न कि वर्ष-वार। इन मिशनों के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए आवंटित केंद्रीय सहायता तथा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान जारी की गई निधि का राज्य-वार विवरण अमृत और अमृत 2.0 के लिए क्रमशः अनुलग्नक III और IV में दिया गया है।

(ग) और (घ) नीति आयोग ने जून 2020 में शहरी परिवर्तन क्षेत्र में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं, जिनमें अमृत भी शामिल है, के मूल्यांकन की समीक्षा की थी। इस अध्ययन में कवरेज, वैश्विक डिजाइन का समावेश, लैंगिक समानता, गरीब-समर्थक डिजाइन, प्रवासन तथा लाभार्थी लक्ष्यीकरण जैसे प्रमुख मापदंडों का आकलन किया गया। योजना के तहत प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया क्योंकि इसका उद्देश्य गरीबों तथा वंचितों सहित सभी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। नीति आयोग ने वर्ष 2025 के दौरान मिशन का मूल्यांकन भी किया है। मूल्यांकन रिपोर्ट से पता चलता है कि मिशन के परिणामस्वरूप कवरेज में वृद्धि हुई है, जलापूर्ति की अवधि और उपयोग के तरीके में

सुधार हुआ है। सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण अवसंरचना संबंधी उपलब्धियां हासिल की गईं हैं।

(ङ) अमृत योजना के अंतर्गत, 9 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 8 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। अमृत योजना 2.0 के अंतर्गत 3,031 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाओं को अनुमोदन दिया जा चुका है, जिनमें से 705 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। अमृत योजना और अमृत योजना 2.0 के अंतर्गत पूर्ण की गई जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाओं का कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-V में दिया गया है।

पार्क एवं हरित स्थान क्षेत्र में, अमृत योजना के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पार्क एवं हरित क्षेत्रों के विकास के लिए 1,606.31 करोड़ रुपये की 2,529 परियोजनाएँ शुरू की हैं। अमृत योजना 2.0 के अंतर्गत, पार्क एवं हरित क्षेत्र में 1,089.31 करोड़ रुपये की 1,669 परियोजनाएँ अनुमोदित की गई हैं। पूर्ण की जा चुकी पार्क परियोजनाओं और अब तक विकसित पार्कों के क्षेत्रफल का कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित राज्य-वार विवरण अनुलग्नक - VI में दिया गया है।

अमृत के अंतर्गत कर्नाटक के बेंगलुरु, दक्षिण कन्नड़ ज़िले तथा अन्य शहरी स्थानीय निकायों में 180 पार्क परियोजनाएँ और एक जलाशय पुनरुद्धार परियोजना पूर्ण की गई हैं।

महाराष्ट्र के जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में अमृत/अमृत 2.0 के अंतर्गत 7 पार्क परियोजनाएँ पूर्ण की गई हैं।

"अमृत मिशन के कार्यान्वयन और परिणामों की स्थिति" के संबंध में दिनांक 18.12.2025 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3064 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक -I

अमृत के तहत जलापूर्ति, सीवरेज, सेप्टेज प्रबंधन और तूफानी जल निकासी परियोजनाओं की प्रगति का राज्य-वार विवरण (20.11.2025 तक)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्र	निर्माणाधीन परियोजनाएं		पूर्ण परियोजना
			सं.	राशि करोड़ रुपये में	राशि करोड़ रुपये में
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	जलापूर्ति	68	6.61	6.35
		जलनिकास	8	4.02	4.02
2	आंध्र प्रदेश	जलापूर्ति	73	2319.77	2,126.71
		सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	40	590.78	362.11
		जलनिकास	14	342.72	198.76
3	अरुणाचल प्रदेश	जलापूर्ति	4	33.12	33.12
		सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	2	53.5	42.08
		जलनिकास	3	40.37	40.37
4	असम	जलापूर्ति	4	609.73	609.73
5	बिहार	जलापूर्ति	37	2306.63	2,266.85
		जलनिकास	3	237.99	211.00
6	चंडीगढ़	जलापूर्ति	7	35.87	35.87
		सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	2	20.2	20.20
7	छत्तीसगढ	जलापूर्ति	84	2048.35	2,038.85
		सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	30	379.17	379.17
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	जलापूर्ति	1	41.28	41.28
		सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	2	21.96	21.96
9	दिल्ली	जलापूर्ति	9	245.64	244.26
		सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	7	408.79	386.88
		जलनिकास	3	5.38	5.38
10	गोवा	जलापूर्ति	3	96.63	92.43
		सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	3	117.53	117.53
11	गुजरात	जलापूर्ति	132	1718.92	1,717.02
		सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	98	2943.89	2,942.26
		जलनिकास	36	224.49	224.03
12	हरियाणा	जलापूर्ति	40	770.19	732.61
		सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	44	1655.23	1,602.68
		जलनिकास	19	452.37	442.04
13	हिमाचल प्रदेश	जलापूर्ति	25	83.3	82.98
		सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	14	99.71	99.71
		जलनिकास	10	31.91	31.91
14	जम्मू और कश्मीर	जलापूर्ति	2	26	26.00

क्रम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्र	निर्माणाधीन परियोजनाएं		पूर्ण परियोजना
		सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	15	137.26	135.98
		जलनिकास	36	184.73	184.73
15	झारखंड	जलापूर्ति	15	1334.18	1,069.68
		सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	9	251.5	200.08
16	कर्नाटक	जलापूर्ति	44	2213.09	2,113.08
		सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	55	2499.92	2,403.01
		जलनिकास	83	238.06	238.06
17	केरल	जलापूर्ति	216	1518.22	1,448.07
		सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	152	385.93	340.46
		जलनिकास	535	363.4	358.38
18	लद्दाख	जलापूर्ति	9	32.15	20.63
		सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	2	4.96	4.93
19	लक्षद्वीप	जलापूर्ति	3	2.34	2.34
20	मध्य प्रदेश	जलापूर्ति	32	2280.8	2,277.93
		सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	29	3882.63	3,658.33
		जलनिकास	23	248.32	248.32
21	महाराष्ट्र	जलापूर्ति	43	4446.06	4,330.77
		सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	36	3294.03	3,200.37
		जलनिकास	1	94.06	94.06
22	मणिपुर	जलापूर्ति	3	207.37	199.08
23	मेघालय	जलापूर्ति	5	22.7	22.52
		सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	2	57.13	57.13
24	मिजोरम	जलापूर्ति	3	51.68	51.68
		सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	3	13.73	13.73
		जलनिकास	3	57.2	57.20
25	नागालैंड	जलापूर्ति	2	8	8.00
		सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	2	8	7.95
		जलनिकास	8	79.75	78.40
26	ओडिशा	जलापूर्ति	130	1535.57	1,535.57
		सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	13	138.21	138.21
27	पुदुचेरी	जलापूर्ति	5	51.03	50.83
		सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	9	11.43	11.07
28	पंजाब	जलापूर्ति	58	1242.28	1,039.97
		सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	62	1504.65	1,449.03
29	राजस्थान	जलापूर्ति	31	1008.22	995.06
		सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	30	2360.19	2,328.55
		जलनिकास	6	63.07	63.07
30	सिक्किम	जलापूर्ति	2	5	5.00
		जलनिकास	25	14.91	14.91
31	तमिलनाडु	जलापूर्ति	18	7436.02	7,330.96
		सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	18	5670.8	5,301.12
32	तेलंगाना	जलापूर्ति	27	1424.09	1,424.09
		सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	4	203.3	203.30

क्रम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्र	निर्माणाधीन परियोजनाएं		पूर्ण परियोजना
33	त्रिपुरा	जलापूर्ति	6	145.19	145.19
		सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	1	11.42	11.42
34	उत्तर प्रदेश	जलापूर्ति	169	4237.56	4,177.38
		सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	159	7353.01	7,196.96
35	उत्तराखंड	जलापूर्ति	47	355.23	352.05
		सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	44	188.1	184.81
		जलनिकास	15	32.57	32.57
36	पश्चिम बंगाल	जलापूर्ति	46	3460.96	3,419.28
		सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	3	192.5	192.50
		जलनिकास	7	301.5	301.50
कुल			3131	80836.06	77,915.45

"अमृत मिशन के कार्यान्वयन और परिणामों की स्थिति" के संबंध में दिनांक 18.12.2025 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3064 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक -II

अमृत 2.0 के तहत जलापूर्ति और सीवरेज, सेप्टेज प्रबंधन की प्रगति का राज्य-वार विवरण (20.11.2025 तक)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जलापूर्ति					सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन				
		अनुमोदित परियोजनाएँ		निर्माणाधीन परियोजनाएं			अनुमोदित परियोजनाएँ		निर्माणाधीन परियोजनाएं		
		सं.	राशि (करोड़ रुपये में)	सं.	राशि (करोड़ रुपये में)	भौतिक रूप से पूर्ण किए गए कार्य (करोड़ रुपये में)	सं.	राशि (करोड़ रुपये में)	सं.	राशि (करोड़ रुपये में)	भौतिक रूप से पूर्ण किए गए कार्य (करोड़ रुपये में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	56	33.94	45	18.85	4.47					
2	आंध्र प्रदेश	240	6,524.47	117	2,003.69	315.96	70	2,468.12	41	525.89	272.35
3	अरुणाचल प्रदेश	7	169.27	7	169.27	23.34					
4	असम	25	876.16	24	818.87	264.84	2	67.34	2	66.42	0.00
5	बिहार	22	3,232.73	3	357.24	0.00	17	5,195.36			
6	चंडीगढ़	2	60.00	1	27.14	1.63	4	115.08	3	78.54	53.49
7	छत्तीसगढ	45	2,362.15	31	1,570.46	538.47	5	645.37	4	495.87	0.00
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव						1	63.47	1	63.47	39.15
9	दिल्ली	2	314.39				38	4,832.35	13	491.17	292.90
10	गोवा	26	149.36	20	124.20	70.45	1	21.26	1	18.47	10.34
11	गुजरात	441	8,670.65	413	8,479.82	4,679.69	167	6,877.24	162	5,734.33	3,240.21
12	हरियाणा	61	2,470.30	53	1,202.96	604.52	16	1,353.24	13	305.10	53.34
13	हिमाचल प्रदेश	17	298.87	17	275.81	143.94	2	11.60	2	11.60	3.87
14	जम्मू और कश्मीर	65	621.90	62	341.31	65.76	3	373.35	3	330.44	22.70
15	झारखंड	17	1,782.03	12	1,526.93	74.79	1	2,284.02			
16	कर्नाटक	227	9,574.39	214	8,559.59	2,478.22					
17	केरल	248	2,412.79	191	1,417.35	654.71	45	1,147.34	28	140.15	34.90
18	लद्दाख	2	707.89				2	192.05	1	61.23	6.07
19	मध्य प्रदेश	297	6,877.53	268	5,965.19	1,256.01	36	5,432.04	17	2,849.57	164.26
20	महाराष्ट्र	116	15,814.93	102	12,170.24	5,492.90	46	12,510.96	34	8,011.87	2,385.01
21	मणिपुर	44	186.85	1	1.48	1.13					
22	मेघालय	1	121.00	1	121.00	105.27					

23	मिजोरम	19	105.81	19	105.81	49.61	1	39.22	1	38.16	7.18
24	नागालैंड	23	111.16	23	97.00	0.00	2	93.92	1	61.63	36.98
25	ओडिशा	212	3,848.76	201	3,577.62	2,057.47					
26	पुदुचेरी	6	79.48	5	62.50	47.37	4	107.14	3	87.42	56.85
27	पंजाब	152	2,980.78	129	1,104.98	408.92	12	541.86	3	189.92	11.08
28	राजस्थान	178	5,099.47	81	1,161.39	80.48	43	5,673.70	37	4,497.72	2,487.23
29	सिक्किम	5	47.37	5	47.36	33.92					
30	तमिलनाडु	201	7,721.59	198	5,993.26	4,347.00	30	6,623.40	29	5,974.67	2,662.70
31	तेलंगाना	98	3,429.04	98	3,429.04	855.92	12	5,775.11	12	5,901.35	201.95
32	त्रिपुरा	9	169.07	9	158.25	133.92					
33	उत्तर प्रदेश	416	21,209.76	308	9,374.08	4,100.86	26	5,054.93	21	2,719.96	1,264.38
34	उत्तराखंड	27	711.19	18	285.57	99.63					
35	पश्चिम बंगाल	209	9,451.54	183	6,955.79	2,634.18	2	341.11	1	84.94	24.91
	कुल योग	3,516	1,18,226.61	2,859	77,504.05	31,625.39	588	67,840.59	433	38,739.90	13,331.85

*लक्षद्वीप ने अनुमोदन के लिए कोई परियोजना प्रस्तुत नहीं की है।

"अमृत मिशन के कार्यान्वयन और परिणामों की स्थिति" के संबंध में दिनांक 18.12.2025 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3064 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक -III

अमृत के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राज्यों को आवंटित और जारी की गई निधि का राज्य-वार विवरण (दिनांक 20.11.2025 तक)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	अमृत के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए कुल केंद्रीय सहायता	पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान परियोजनाओं के लिए जारी केंद्रीय सहायता
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह*	10.82	-
2	आंध्र प्रदेश	1,056.62	183.5
3	अरुणाचल प्रदेश	126.22	17.37
4	असम	591.42	258.84
5	बिहार	1,164.80	90.28
6	चंडीगढ़*	54.09	-
7	छत्तीसगढ़*	1,009.74	-
8	दादरा और नगर हवेली*	10.82	-
	दमन और दीव	18.03	14.43
9	दिल्ली	802.31	155.53
10	गोवा	104.58	41.84
11	गुजरात	2,069.96	300
12	हरियाणा	764.51	9.43
13	हिमाचल प्रदेश*	274.07	-
14	जम्मू और कश्मीर*	500.62	-
15	लद्दाख	79.19	1.8
16	झारखंड*	566.17	-
17	कर्नाटक*	2,318.79	-

18	केरल	**1,161.20**	**207.23**
19	लक्षद्वीप*	**3.61**	**-**
20	मध्य प्रदेश*	**2,592.86**	**-**
21	महाराष्ट्र	**3,534.08**	**249.94**
22	मणिपुर*	**162.28**	**-**
23	मेघालय	**72.12**	**39.42**
24	मिजोरम	**126.22**	**5.65**
25	नागालैंड	**108.19**	**30.69**
26	ओडिशा*	**796.97**	**-**
27	पुदुचेरी	**64.91**	**19.66**
28	पंजाब	**1,204.47**	**204.87**
29	राजस्थान	**1,541.95**	**53.26**
30	सिक्किम	**36.06**	**2.97**
31	तमिलनाडु	**4,756.58**	**828.95**
32	तेलंगाना*	**832.6**	**-**
33	त्रिपुरा*	**133.43**	**-**
34	उत्तर प्रदेश	**4,922.46**	**1,027.09**
35	उत्तराखंड*	**533.72**	**-**
36	पश्चिम बंगाल*	**1,929.32**	**-**
कुल		**36,035.79**	**3,742.73**

*- पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 22-23, 23-24 और 24-25) में इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अमृत परियोजनाओं के लिए कोई भी केंद्रीय सहायता जारी नहीं की गई है।

"अमृत मिशन के कार्यान्वयन और परिणामों की स्थिति" के संबंध में दिनांक 18.12.2025 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3064 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक -IV

अमृत 2.0 के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राज्यों को आवंटित और जारी की गई निधि का राज्यवार विवरण (दिनांक 20.11.2025 तक)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य	अमृत 2.0 के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान परियोजनाओं के लिए जारी केंद्रीय सहायता
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	36	5.51
2	आंध्र प्रदेश	2948	589.55
3	अरुणाचल प्रदेश	226	29.5
4	असम	775	165.68
5	बिहार	2628	410.77
6	चंडीगढ़	170	33
7	छत्तीसगढ	1303	182.52
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	30	6
9	दिल्ली	2885	282.66
10	गोवा	85	15.76
11	गुजरात	4512	1305.47
12	हरियाणा	1496	245.14
13	हिमाचल प्रदेश	256	127.67
14	जम्मू और कश्मीर	867	158.6
15	झारखंड	1183	38.99
16	कर्नाटक	4628	1294.04
17	केरल	1374	205.44
18	लद्दाख	128	11.7
19	लक्षद्वीप*	2	0
20	मध्य प्रदेश	4065	153.77
21	महाराष्ट्र	9310	2133.66
22	मणिपुर	170	17.05
23	मेघालय	111	86.77
24	मिजोरम	143	28
25	नागालैंड	176	35.19
26	ओडिशा	1373	396.57
27	पुदुचेरी	150	47.04
28	पंजाब	1836	254.69

29	राजस्थान	3552	695.45
30	सिक्किम	40	8
31	तमिलनाडु	4942	1614.93
32	तेलंगाना*	2789	0
33	त्रिपुरा	157	79.11
34	उत्तर प्रदेश	8161	1296.67
35	उत्तराखंड	585	75.92
36	पश्चिम बंगाल	3658	495.65
	कुल	**66,750**	**12,526.47**

*- पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 22-23, 23-24 और 24-25) में इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अमृत 2.0 परियोजनाओं के लिए कोई केंद्रीय सहायता जारी नहीं की गई है।

"अमृत मिशन के कार्यान्वयन और परिणामों की स्थिति" के संबंध में दिनांक 18.12.2025 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3064 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक - V

अमृत परियोजना के अंतर्गत पूर्ण की गई जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या

(दिनांक 20.11.2025 तक)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पूर्ण हो चुकी जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाओं की संख्या
1	बिहार	1
2	दिल्ली	1
3	कर्नाटक	1
4	केरल	4
5	उत्तर प्रदेश	1
	कुल योग	**8**

अमृत 2.0 के अंतर्गत पूर्ण की गई जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पूर्ण हो चुकी जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाओं की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	69
2	अरुणाचल प्रदेश	2
3	असम	13
4	दिल्ली	15
5	गुजरात	49
6	हिमाचल प्रदेश	10
7	जम्मू और कश्मीर	15
8	झारखंड	24
9	केरल	77
10	मध्य प्रदेश	120
11	महाराष्ट्र	11
12	ओडिशा	4
13	पुदुचेरी	3
14	राजस्थान	18
15	सिक्किम	1
16	तमिलनाडु	269
17	त्रिपुरा	2
18	पश्चिम बंगाल	3
	कुल योग	**705**

"अमृत मिशन के कार्यान्वयन और परिणामों की स्थिति" के संबंध में दिनांक 18.12.2025 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3064 के भाग (ड़) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक - VI

राज्य-वार पूर्ण की गई पार्क परियोजनाओं और विकसित पार्कों के क्षेत्रफल का विवरण (दिनांक 20.11.2025 तक)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पूर्ण अमृत पार्क परियोजना		पूर्ण अमृत 2.0 पार्क परियोजना	
		सं.	पार्कों का क्षेत्रफल (एकड़ में)	सं.	पार्कों का क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	0.22		
2	आंध्र प्रदेश	97	204.44		
3	अरुणाचल प्रदेश	2	1.95	8	988.42
4	असम	13	13.31		
5	बिहार	25	65.52		
6	चंडीगढ़	3	0.77		
7	छत्तीसगढ	191	349.79		
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	2	0.69		
9	दिल्ली	7	195.62	2*	3.27*
10	गोवा	2	1.98		
11	गुजरात	124	997.20	60	839.56
12	हरियाणा	33	15.40		
13	हिमाचल प्रदेश	9	2.84	7	57.82
14	जम्मू और कश्मीर	14	5.13		
15	झारखंड	35	84.86		
16	कर्नाटक	180	347.76		
17	केरल	78	55.21		
18	लद्दाख	6	25.06		
19	लक्षद्वीप	3	1.27		
20	मध्य प्रदेश	110	422.04	188	904.37
21	महाराष्ट्र	128	454.92	2	1.47
22	मणिपुर	1	3.65		
23	मेघालय	8	1.76		
24	मिजोरम	4	8.49		
25	नागालैंड	10	5.10		
26	ओडिशा	48	116.69		
27	पुदुचेरी	9	4.10		
28	पंजाब	35	54.32		
29	राजस्थान	77	298.02	1	0.47
30	सिक्किम	3	0.03		

31	तमिलनाडु	409	337.64	469	383.02
32	तेलंगाना	35	442.43		
33	त्रिपुरा	3	4.51		
34	उत्तर प्रदेश	320	470.08		
35	उत्तराखंड	42	36.00		
36	पश्चिम बंगाल	420	241.65	1	1.73

*संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 04.12.2025 को दी गई जानकारी के अनुसार